जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

जालोर

Rashtradoot

फोनः- 226422, 226423 फैक्सः- 02973-226424 वर्षः 19 संख्याः 300 प्रभात जालोर, बुधवार 5 फरवरी, 2025 पो. रजि. /RJ/SRO/9640/2022-24 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

आखिर राहुल गांधी, वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के दबाव में क्यों नहीं आये?

इन नेताओं का दबाव था कि राहुल पूरा जोर न लगायें आप के खिलाफ दिल्ली में, क्योंकि इसका लाभ भाजपा को ही होगा

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 4 फरवरी। दिल्ली में वोट कल डाले जायेंगे। यूँ तो दिल्ली विधानसभा में मात्र 70 सीटें हैं, लेकिन दिल्ली के चुनाव राजनैतिक हल्कों में चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बने हुये हैं।

चुनाव प्रचार के पिछले एक महीने में परिदृश्य काफी बदला है। जो चुनावी लड़ाई आम आदमी पार्टी तथा भाजपा के बीच मानी जा रही थी, वह कांग्रेस के चुनाव में सक्रिय होने के कारण त्रिकोणीय हो गई है। गांधी भाई-बहिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी को ललकार रहे हैं तथा उस पर भ्रष्टाचार का मूल स्त्रोत होने का आरोप लगा रहे हैं और इस बदलाव का श्रेय केवल एक ही कांग्रेस नेता को जाता है, वो हैं संदीप दीक्षित।

संदीप दीक्षित ने अपनी सक्रियता नई दिल्ली से शुरू की। अरविन्द केजरीवाल को टक्कर देने के लिये, उन्होंने घर-घर जाकर प्रचार किया, लोगों के साथ बैठकें की तथा आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के खिलाफ "एकला चालो" की नीति पर चलते रहे।

उन्होंने कांग्रस को यह महसूस करा दिया कि आम आदमी पार्टी से टक्कर लेना सम्भव है और यह चुनाव एक हारी

- पर, हरियाणा के विधानसभा चुनाव में आप ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए और इसका अंततोगत्वा नतीजा यह निकला था कि हर "कॉन्स्टिटुएंसी" पर आप ने कांग्रेस के वोट काटे तथा कांग्रेस सरकार नहीं बना सकी, जिसकी सबको "उम्मीद सी" थी।
- राहुल ने हरियाणा का बदला लेने का मन बनाया दिल्ली में, क्योंकि राहुल के समझ में आ गया कि आप कांग्रेस की कोई मित्र नहीं, बल्कि सदा कांग्रेस के वोट काट कर ही आगे बढ़ी है।
- कांग्रेस में गंभीरता से चुनाव जीतने के लिए लड़ने का उत्साह भरने में संदीप दीक्षित की भी भूमिका रही। संदीप पहले ही दिन से "डोर-टु-डोर" जनसंपर्क कर चुनाव प्रचार में लगे तथा हाईकमान को "कन्विन्स" करने में सफल हुए कि कांग्रेस चुनाव में निरीह पार्टी नहीं बल्कि निर्णायक भूमिका निभाने की स्थिति में है।

हुई लड़ाई हरगिज नहीं है।

वरिष्ठ नेतागण भी प्रचार के लिये भेजे गये, लेकिन उनमें से अधिकांश इस चुनाव को एक हारी हुई लड़ाई माने हुये थे, लेकिन नेतृत्व इस बात को लेकर दृढ़प्रतिज्ञ था कि कांग्रेस, भाजपा और आप के खिलाफ अपना सब कुछ दाँव पर लगा देगी।

पिछले दो चुनावों में कांग्रेस का पूरी तरह सफाया हो गया था, उसे एक भी सीट नहीं मिली थी। तथा कांग्रेस सिर्फ इसलिये आप का सामना करना नहीं चाहती थी कि वह भाजपा को दिल्ली की सत्ता से दूर रखना चाहती थी।

लेकिन जब आप ने हरियाणा के चुनावों में हर सीट पर अपने प्रत्याशी खड़े किये, जिससे भाजपा को मदद मिली तथा कांग्रेस को हार का मुँह देखना पड़ा, उस समय यह स्पष्ट हो गया कि केजरीवाल कांग्रेस के मित्र नहीं हैं, वे भाजपा की मदद करते हैं।

आम आदमी पार्टी ने अस्तित्व में आने के बाद कांग्रेस के वोट बैंक पर कब्जा कर लिया, और 15 साल दिल्ली की सत्ता में रहने के बाद, ऐसा लगा कि कांग्रेस सब कुछ खो चुकी है।

इस बार कम से कम 15 सीटों पर कांग्रेस की स्थिति ठीक-ठाक दिखाई दे रही है, लेकिन इसका प्रदर्शन कैसा रहेगा, इसे कितने वोट मिलेंगे, यह तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा।

भाजपा, जो 26 साल से दिल्ली की सत्ता से बाहर है, ने राजधानी की सत्ता में आने के लिये अपना सब कुछ चुनाव में झौंक दिया है, मध्यम वर्ग को इन्कम टैक्स में राहत का तोहफा देकर अपनी ओर खींचने की कोशिश की है। उसने आशा सँजो रखी है कि कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन से आप नुकसान होगा तथा भाजपा को अप्रत्यक्ष मदद मिलेगी।

चुनाव की उत्तेजना अपने चरम पर रही है, राहुल और प्रियंका गांधी की सभाओं में जबरदस्त भीड़ एकत्रित हुई है, जबकि आप के वरिष्ठ मंत्रियों तक को

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जल जीवन मिशन में महेश मित्तल को भी जमानत मिली

जयपुर, 4 फरवरी। राजस्थान हाईकोर्ट ने जल जीवन मिशन में फर्जी दस्तावेजों के जरिए टेंडर लेने से जुड़े ईडी के मामले में आरोपी महेश मित्तल को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकलपीठ ने गत 31 जनवरी को सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

जमानत याचिका में अधिवक्ता विवेक राज बाजवा ने अदालत को बताया कि मामले में सुप्रीम कोर्ट से पदम चंद जैन, पीयूष जैन और संजय बड़ाया को जमानत मिल चुकी है। इसके

- सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में पदम चंद जैन, पीयूष जैन व संजय बडाया को पहले जमानत मिल चुकी है।

अलावा, यदि संजय बडाया के जरिए तत्कालीन मंत्री महेश जोशी को रुपए देना बताया जा रहा है तो फिर महेश जोशी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पदम चंद जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए इस बिंदु पर सवाल खड़ा किया था। याचिका में यह भी कहा गया कि महेश मित्तल को जेल में रखने से उसके संविधान प्रदत्त अनुच्छेद 21 के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

याचिका का विरोध करते हुए, ईडी की ओर से एएसजी राज दीपक रस्तोगी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ट्रम्प केवल बड़बोले नेता नहीं, बल्कि एक चतुर राजनीतिज्ञ भी हैं?

ट्रम्प ने कैनडा व मैक्सिको पर टैरिफ लगाने के निर्णय का क्रियान्वयन एक महीना सशर्त आगे खिसकाया

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 4 फरवरी। पुनः निर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप, जितना समझा जाता है उससे कहीं अधिक चतुर राजनेता हैं।

डॉनल्ड ट्रंप ने अब मैक्सिको और कैनडा से आयातों पर तत्काल टैरिफ वृद्धि के अपने प्रस्तावों को रोक दिया है, इस शर्त पर कि दोनों देश अमेरिका की आपत्तियों को हल करने की दिशा में और कदम उठाएंगे।

चीन के मामले में स्थिति अलग है। ट्रंप अभी भी चीन पर टैरिफ लागू करने पर जोर दे रहे हैं और चीन ने इसके जवाब में संयुक्त राज्य अमेरिका से आयातों पर 10 प्रतिशत का नया टैरिफ लागू कर दिया दिया है। हालांकि, चीन ने 20 बिलियन डॉलर मूल्य के आयातों पर टैरिफ लगाए हैं, जबकि अमेरिकी टैरिफ चीन से आयात होने वाले 450 बिलियन डॉलर मूल्य के सामान पर होंगे।

चीन ने अमेरिका के खिलाफ अपने विरोध और चुनौती को दिखाने के लिए टैरिफ बढ़ाए हैं। इससे अमेरिकी अधिकारियों के साथ वार्ता के लिए

- शर्त यह है कि दोनों देश, अमेरिका को विश्वास दिलायेंगे कि अमेरिका के हितों के साथ सामंजस्य बिठाकर ही अपने व्यापार व उद्योग की नीति बनायेंगे और उन नीतियों पर पूर्ण ईमानदारी से काम करेंगे।
- चीन भी अमेरिका के बढ़ाये गये टैरिफ को मन ही मन स्वीकार तो कर रहा है, पर, यह छवि नहीं बनने देना चाहता है कि उसने अमेरिका के दबाव के आगे घुटने टेक दिये। अतः चीन कुछ विरोध जताने को सार्वजनिक मुद्दा बनाये हुए है। उदाहरण के लिये, चीन ने अमेरिका से आयात पर दस प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की, पर, निर्णय बेमाने हैं, यह टैरिफ केवल 10 अरब डॉलर अमेरिकी गुड्स पर ही लगेगा, क्योंकि इतना ही आयात है चीन में अमेरिका से। पर, अमेरिका को चीन 450 अरब डॉलर का माल निर्यात करता है। अतः, अमेरिका के 10 प्रतिशत टैरिफ बढ़ाने से चीन से निर्यात माल बहुत महंगा हो जायेगा।
- यह टैरिफ वृद्धि, जो अमेरिका ने लगाई थी, वह एक महीने बाद लागू होगी और ट्रम्प ने कहा है, वह एक महीने में इन देशों का आचरण देखकर आगे क्या करना है, इसका निर्णय लेंगे।

अवसर बचा हुआ है, ताकि मुद्दों को हल

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एल एण्ड टी, बी.ई.एल. व सीमैंस के शेयर के दाम बढ़ेंगे, केन्द्रीय बजट 2025 के बाद?

वित्त मंत्री द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर (सड़क, रेलवे व शहरी यातायात) पर भारी बजट एलोकेशन करने से, कैपिटल गुड्स, डिफैन्स व इलैक्ट्रोनिक्स के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों को अपना भविष्य उज्ज्वल नज़र आ रहा है

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 4 फरवरी। हाल ही में प्रस्तुत 2025 के केन्द्रीय बजट ने भारत के सतत आर्थिक विकास का रोड मैप प्रस्तुत किया है जिसमें कुछ प्रमुख क्षेत्रों के फलने -फूलने के लिए अनुकूल माहौल दिया गया है। उम्मीद है कि विभिन्न उद्योगों के प्रमुख स्टॉक्स सरकार के सुधारो, प्रोत्साहनों और इन्फ्रास्ट्रक्चर, हरित ऊर्जा व डिजीटल बदलाव सार्वजनिक खर्च में वृद्धि से उत्पन्न रणनीतिक परिवर्तनों के साथ बजट के बाद के आर्थिक परिदृश्यों में आगे बढ़ेंगे।

बजट का इन्फ्रास्ट्रक्चर (बुनियादी ढांचे) के विकास पर जोर, जिसमें सड़कें, रेलमार्ग और शहरी परिवहन शामिल हैं, निर्माण और इंजीनियरिंग क्षेत्रों की कंपनियों के लिए एक प्रमुख

- सीमेंट, स्टील में कारोबार करने वाली कम्पनियां, जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट व टाटा स्टील के शेयर्स के लिये भी शुभ दिनों का आगमन संभव है।
- एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक व स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सुखद स्थिति में रहेंगे, क्योंकि वे डिजिटल फाइनैंशियल इन्फ्रास्ट्रक्चर में डील करने वाली कम्पनियों को व्यापार के लिये और अधिक व आसानी से वित्तीय पूँजी उपलब्ध कराने का इरादा जता रहे हैं।

लाभ है। प्रमुख स्टॉक्स जैसे लार्सन एंड टुब्रो (एल एण्ड टी) को अवसरों का फायदा मिल सकता है।

एल एण्ड टी के सीईओ एस.एन. सुब्रमण्यन ने कहा, "इन्फ्रास्ट्रक्चर को जो प्रोत्साहन दिया गया है वह हमें विकास के अवसर प्रदान करेगा। हमें विश्वास है कि इससे हमारे मुख्य इंजीनियरिंग और निर्माण सेवाओं की मांग में वृद्धि होगी।"

बजट का "मेक इन इंडिया" पर जोर और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन, कॅपिटल गुड्स, रक्षा और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों की कंपनियों के लिए शुभ संकेत हैं। भारत

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

गोगामेडी हत्याकांड की महिला आरोपी को जमानत नहीं

जयपुर, 4 फरवरी। एनआईए मामलों की विशेष अदालत ने सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में शामिल शूटर को शरण देने और उसकी देखरेख के आरोप में जेल में बंद महिला आरोपी पूजा सैनी की द्वितीय जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। पीठासीन अधिकारी रेखा भार्गव ने कहा कि केस की परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं

- गत 10 अक्टूबर को आरोपी पूजा सैनी की पहली जमानत अर्जी खारिज हुई थी।

हुआ है। ऐसे में घटना की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। आरोपी पूजा की गत 10 अक्टूबर को पहली जमानत अर्जी खारिज हुई थी।

गौरतलब है कि पांच दिसंबर, 2023 को रोहित और नितिन ने श्याम नगर थाना इलाके में घर में घुसकर सुखदेव सिंह गोगामेडी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस दौरान वहां मौजूद नवीन शेखावत की भी गोली लगने से मौत हो गई थी। घटना को लेकर पुलिस ने दोनों शूटरों सहित पांच अन्य

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

वातावरण में बढ़ता प्रदूषण व यमुना का "दूषित" पानी अंत में कोई मुद्दा नहीं बना दिल्ली के चुनाव में

जैसे-जैसे मतदान का दिन नज़दीक आने लगा, ये मुद्दे राजनीतिज्ञों के भाषणों से नदारद से हो गए

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 4 फरवरी। दिल्ली विधानसभा चुनावों के प्रचार की समाप्ति से कुछ दिन पहले, दो मुद्दे चर्चा में थे- हरियाणा की फैक्ट्रियों का विषैला औद्योगिक कचरा जो यमुना नदी में डाला जा रहा है, जबकि यमुना पहले ही प्रदूषित है तथा दूसरा ज्वलंत मुद्दा था कि दिल्ली की हवा की गुणवत्ता दिन पर दिन खराब होती जा रही है। तीन दिन तक ये दोनों मुद्दे तीखी बहस के केन्द्र में बने रहे और उसके बाद ये दोनों मुद्दे चर्चा से गायब हो गये, मानो ये मुद्दे इतने गंभीर नहीं थे कि दिल्ली के मतदाता इनके आधार पर वोट डालने का निर्णय लें।

सात जनवरी, जिस दिन चुनाव आयोग ने दिल्ली के चुनावों का कार्यक्रम घोषित किया था, उसी दिन ही सैन्टर फॉर साइंस एंड एनवायरनमैंट (सीएसई) ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें दिल्ली में खराब होती जा रही हवा की गुणवत्ता

- मुख्य मुद्दा रह गया कौन कितनी "रेवड़ी" बांटने का वादा कर रहा है।
- दिल्ली की आबादी का 40 प्रतिशत हिस्सा अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण करके बनाई गई बस्तियों में रहता है, जिसके लिये पानी, बिजली, राशन ही मुख्य मुद्दा है और आप द्वारा इन क्षेत्रों में दी गई "सुविधाओं" के कारण यह आप का परमानैंट वोट बैंक है। शीला दीक्षित के समय यह कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था, पर, गत 15 साल से ये आप के वफादार वोटर हैं। पर, क्या वर्तमान चुनाव में भी वे आप के साथ ही रहेंगे?

के कारण जनता के स्वास्थ्य को लेकर गहरी चिन्ता व्यक्त की गई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि पीएम 2.5 या इससे अधिक कन्सनट्रेशन वाला एयर क्वालिटी लेवल खतरनाक माना जाता है। रिपोर्ट में आगे यह भी बताया गया था कि गत वर्ष अक्टूबर से दिसम्बर के बीच, मॉनिटरिंग स्टेशनों पर पॉल्यूशन लेवल में 26 प्रतिशत की खतरनाक वृद्धि रिकॉर्ड की गई थी। लेकिन पिछले सप्ताह संसद में पेश किये गये केन्द्रीय बजट में दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिये न तो कोई विशेष बजट प्रावधान किये गये और न इस मुद्दे से निबटने के लिये वचनबद्धता जैसी कोई चीज ही नज़र आई।

दिल्ली में चुनाव प्रचार सोमवार को समाप्त हो गया और 5 फरवरी को मतदान हो जायेगा, लेकिन दिल्ली का एयर क्वालिटी इनडैक्स (एक्यूआई) 355 के खतरनाक स्तर पर पहुँच गया। स्मॉग और प्रदूषण से आसमान ढ़क गया है तथा भविष्यवाणियाँ और भी ज्यादा खराब हालत की ओर संकेत कर रही हैं। पिछले कुछ दिनों में, अस्पतालों में आँखों में जलन और श्वास लेने में दिक्कत की शिकायत करने वाले मरीज बढ़े हैं।

आम आदमी पार्टी तथा भारतीय जनता पार्टी के बीच चन्द रोज इस विषय को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर चला था। इस बीच, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी अंतिम चुनावी रैलियों में इस बिन्दु को लेकर केजरीवाल सरकार पर निरन्तर प्रहार किये तथा शहर के धूल-धक्कड़ तथा प्रदूषित हवा में साँस लेने में कठिनाई पर फोकस किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी जनता की सहानुभूति प्राप्त करने के इस अवसर पर चूके नहीं, उन्होंने केजरीवाल से सार्वजनिक रूप से पूछ ही

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

205 अवैध प्रवासी भारतीयों को अमेरिका ने डिपोर्ट किया

वाशिंगटन, 04 फरवरी। अमेरिका के नये राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त सामूहिक निर्वासन अभियान के तहत एक अमेरिकी सैन्य सी-17 विमान 205 अवैध प्रवासी भारतीयों को लेकर भारत

- अमेरिका का सैन्य विमान सी-17 इन भारतीयों को लेकर भारत आ रहा है और सूत्रों के अनुसार विमान अमृतसर में उतर सकता है।

के लिए रवाना हो गया है।

इन सभी की पहचान के बाद डिपोर्ट किया गया है। सूत्रों के अनुसार विमान अमृतसर में लैंड करेगा। पश्चिमी मीडिया की ओर से जारी एक रिपोर्ट में एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से मंगलवार को यह जानकारी दी गयी।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

शारीरिक शिक्षक भर्ती-2022 धांधली को लेकर 40 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की

इन अभ्यर्थियों ने फर्जीवाड़े से नौकरी पाने वाले शिक्षकों को बर्खास्त करने और उनकी जगह नियुक्ति देने की गुहार लगाई

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर, 4 फरवरी। शारीरिक शिक्षक (पी.टी.आई.) भर्ती-2022 में धांधली और फर्जी दस्तावेजों से नौकरी पाने वाले लोगों के खिलाफ 40 अभ्यर्थियों ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं ने पिछली गहलोत सरकार द्वारा इस भर्ती को रद्द नहीं किये जाने के फैसले को चुनौती दी है, साथ ही फर्जी दस्तावेजों और धांधली से नौकरी पाने वाले करीब 2000 लोगों को बर्खास्त करने की गुहार लगायी है। याचिकाओं में कहा गया है, इस भर्ती परीक्षा की पूरी जांच एस.ओ.जी. राजस्थान हाईकोर्ट की निगरानी में करे। अदालत एस.ओ.जी. द्वारा की गई अब तक की जांच का रिकॉर्ड भी मंगवाएं। इन 40 याचिकाकर्ताओं ने गुहार लगायी है कि धांधली से नौकरी करने वालों को बर्खास्त करने के बाद, उनकी जगह पर हमें नियुक्ति दी जाये। यह रिट याचिका अधिवक्ता हरेन्द्र नील ने दायर की थी।

याचिकाकर्ताओं की ओर से बताया गया है कि इस भर्ती में फर्जीवाड़े से करीब 2000 लोगों ने नौकरी प्राप्त की है। एस.ओ.जी. ने 10 जून 2024 को इस मामले की जांच करते हुए एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें साफ लिखा था कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ से फर्जी डिग्रियां लेकर नौकरी हासिल की गई हैं। इनमें से 145 अयोग्य अभ्यर्थियों के पास ओ.पी.जे.एस. यूनिवर्सिटी की डिग्री थी, जबकि अंतिम सूची में मात्र 6 ऐसे योग्य अभ्यर्थी थे, जिनके पास इस यूनिवर्सिटी की डिग्री थी। करीब 173 ऐसे अयोग्य अभ्यर्थी थे, जिन्होंने परीक्षा के बाद डिग्रियां ली थीं। कुछ लोग ऐसे थे, जिनके पास ऐसी यूनवर्सिटी की डिग्रियां थी, जो कि एन.सी.टी.ई. (नैशनल काउन्सिल फॉर टीचर एजुकेशन) द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं थीं। इसी प्रकार, 183 अयोग्य अभ्यर्थी ऐसे थे, जिनके पास बी.पी.एड. डिग्री में 45 प्रतिशत से भी कम अंक आए थे। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 1259 अयोग्य अभ्यर्थियों को शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति दी गई है, इनमें से 1230 लोग ऐसे हैं, जिनके आवेदन और डिग्रियों में अंक प्रतिशत व रोल नंबर की गड़बड़ियां हैं। याचिका में कहा गया कि एस.ओ.जी. की इस जांच रिपोर्ट के निष्कर्षों को भी लागू किया जाए। इससे स्पष्ट दिख रहा है कि 2000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने फर्जीवाड़े से नौकरी पायी है। गौरतलब है कि याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने अभी तक मात्र 58 अयोग्य शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।

अदालत में पेश हुई इन 40 रिट याचिकाओं के अलावा करीब 15-20 याचिकाएं, ऐसी भी हैं, जिनमें जांच

- अदालत में पेश हुई इन 40 रिट याचिकाओं के अलावा करीब 15-20 याचिकाएं, ऐसी भी हैं, जिनमें जांच कमेटी द्वारा नियुक्त किए जा चुके पी.टी.आई. शिक्षकों को बर्खास्त करने के लिए "कारण बताओ नोटिस" दिए गए थे।
- याचिकाकर्ताओं का कहना है कि एस.ओ.जी. ने 10 जून 2024 को एक जांच रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें स्पष्ट लिखा था कि 1259 अयोग्य अभ्यर्थियों को शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति दी गई है, इनमें से 1230 लोग ऐसे हैं, जिनके आवेदन और डिग्रियों में अंक प्रतिशत व रोल नंबर की गड़बड़ियां हैं। याचिका में कहा गया कि, एस.ओ.जी. की इस जांच रिपोर्ट को भी लागू किया जाए।
- उल्लेखनीय है कि, न्यायाधीश अनूप कुमार ढंढ ने इस प्रकरण में अलग-अलग तारीखों पर 134 पी.टी.आई. शिक्षकों को जांच के बाद पद से हटाने के आदेश दिए थे। हालांकि, करीब 33 ऐसे शारीरिक शिक्षक हैं, जिन्होंने अदालत से स्टे ले रखा है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास की सजा

जयपुर, 4 फरवरी। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत, क्रम-2 महानगर प्रथम, ने 11 साल की नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त रूप सिंह बैरवा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, अदालत ने अभियुक्त पर 51 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने, जानकारी

- चार दिन बाद रिपोर्ट दर्ज करने पर शिप्रा पथ के तत्कालीन थानाधिकारी को नोटिस जारी।

मिलने के बाद चार दिन तक रिपोर्ट दर्ज नहीं करने पर शिप्रापथ थाने के तत्कालीन थानाधिकारी को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न इस मामले में उनके खिलाफ अलग से मुकदमा शुरू किया जाए। पीठासीन अधिकारी तिरुपति कुमार गुप्ता ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त की आपराधिक मानसिकता इस बात से

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)